

>

Title: Need to restart the closed cloth mills of Indore, Madhya Pradesh and also give the workers of the closed Mills their dues.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): इन्दौर शहर पूर्व में मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कपड़ा उद्योग के नाम से विख्यात रहा है। इन्दौर शहर में कपड़ा उद्योग लगातार लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहा। लगभग 40 वर्ष पूर्व कपड़ा उद्योग में आई मंटी एवं गिरावट के दौर में इन्दौर की मिलों भी इससे अल्पी नहीं रही और मिलों पाटे में आने लगी। तब देश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न रव. श्रीमती इनिदरा गांधी जी ने मध्य प्रदेश की 7 मिलों के साथ ही इन्दौर के 3 मिलों का भी राष्ट्रीयकरण सन् 1972 में किया था। मिलों का राष्ट्रीयकरण करके केन्द्र में राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग निगम (एन.टी.सी.) का गठन किया और इसी निगम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत मिलों का संचालन भी किया जाता रहा। सन् 2002 में एन.टी.सी. द्वारा इन्दौर की तीनों मिलों (मालवा मिल, कल्याण मिल, रवदेशी मिल) को बंद कर दिया गया। मिलों बंद करते समय कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो योजना बनाई गई थी उसमें इन्दौर की एक मिल को चलाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। किंतु कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसके बाद भी इन्दौर की एक भी मिल चालू नहीं की गई और न ही इसके लिए कोई कार्रवाही की गई। इसकी वजह से छजारों मिल मजदूर बेरोजगार हो गए और इनके पाठार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं तथा इस वजह से आज तक रैंकड़ों मजदूर आत्म-हत्या कर चुके हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक परीक्षण दल भेजकर कपड़ा मिल चालू करवाने की पहल करें एवं अपने वादे को निभाए तथा मध्य प्रदेश सरकार को इन्दौर की बंद पड़ी डुकुमचंद मिल की जमीन बेचकर मजदूरों के हक का 229 करोड़ रुपया ठिलवाने हेतु निर्देशित करें।